PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 320 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शुक्रवार 05 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

सरहद पर बुनियादी सुविधाओं की तारबंदी...

तरसते लोग, सिसकते गांव!

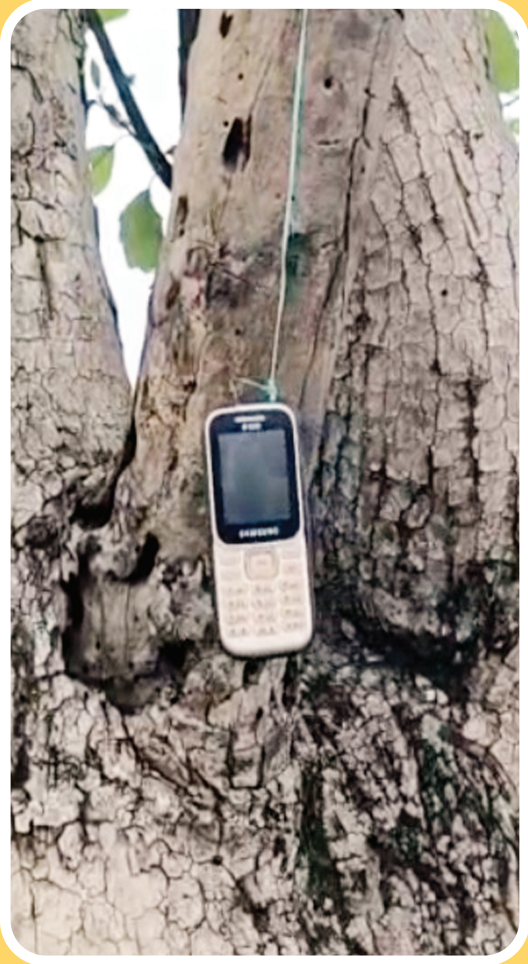

थार के सीमांत पर विकास का ‘डिजिटल ब्लैकआउट’

दावों की चमक के बीच अंधेरे में जी रहे देश के ‘पहले प्रहरी’ भारतीय नेटवर्क गायब पर पाकिस्तानी सिग्नल मजबूत

बॉर्डर पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर ग्राउंड रिपोर्ट...

मनोहरसिंह खोखर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा (बाड़मेर-जैसलमेर)

सरहद पर लगी कटीली तारें सिर्फ दुश्मनों को नहीं रोक रहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वे विकास और बुनियादी सुविधाओं को भी इन गांवों में आने से रोक रही हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में आज भी ‘डिजिटल इंडिया’ एक सपना है। यहाँ भारतीय कंपनियों का नेटवर्क पूरी तरह गायब है, जबकि पाकिस्तानी मोबाइल सिग्नल पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते सूखे कंठ और संचार के इस ‘ब्लैकआउट’ के बीच, देश के ये ‘पहले प्रहरी’ अब पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे सीमांत क्षेत्र की ढाणियां तेजी से सूनी हो रही हैं। जहां थार का रेगिस्तान और अंतरराष्ट्रीय सीमा की कटीली तारें आपस में मिलती हैं, वहां विकास के सरकारी दावों की कलई खुल जाती है। देश की मुख्यभूमि पर ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘हर घर जल’ का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी सीमा के इन आखिरी गांवों में हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

‘नो नेटवर्क जोन’

भारतीय नेटवर्क गायब, पाकिस्तानी सिग्नल मजबूत

सीमावर्ती गांव बच्चियां, सुंदरा, सरूपे का तला और गजुओं की बस्ती में कदम रखते ही मोबाइल फोन नेटवर्क ने दम तोड़ दिया। डिजिटल इंडिया और 5त्न क्रांति के इस दौर में बाड़मेर-जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके आज भी ‘डिजिटल ब्लैकआउट’ का दंश झेल रहे हैं। भारत की संचार कंपनियों के टावर इन दूरदराज के क्षेत्रों में शोपीस बने हुए हैं।

ग्रामीणों को अपने परिजनों से बात करने या किसी आपात स्थिति में प्रशासन को सूचना देने के लिए ऊंचे रेतीले टीलों, पानी की टंकियों या खेजड़ी के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों का कहना है कि भारतीय नेटवर्क के सिग्नल भले ही न मिलें, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान की मोबाइल कंपनियों (जैसे जैज और यूफोन) के सिग्नल इन भारतीय गांवों में पूरी ताकत के साथ पकड़ में आ जाते हैं। यह स्थिति न केवल स्थानीय संचार को ठप करती है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी एक बेहद संवेदनशील और गंभीर खतरा है।

नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग

यहां ‘डिजिटल ब्लैकआउट’ है और बुनियादी हक दूर की कौड़ी बने हुए हैं। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तो मुस्तैदी से वतन की रक्षा करते ही हैं, लेकिन उनके समानांतर इन सीमाओं पर बसे गांवों के नागरिक देश का ‘पहला रक्षा कवच’ कहलाते हैं। देश में आजादी का अमृत काल बीत चुका है और सरकारें ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत सीमांत क्षेत्रों के कायाकल्प के बड़े-बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन धरातल की कड़वी सच्चाई यह है कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के दूरदराज बॉर्डर इलाकों में रहने वाले बाशिंदे आज भी आदिम युग जैसी परिस्थितियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तपते रेगिस्तान के बीच बसी इन ढाणियों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी एक क्रूर मजाक बनी हुई हैं। यदि देश की इस सामरिक रूप से सबसे संवेदनशील पश्चिमी सीमा को अभेद्य और सुरक्षित रखना है, तो केवल चौकियों पर जवानों को तैनात करना काफी नहीं होगा। इन सीमाओं पर विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों में डटे देश के इन असली प्रहरियों (नागरिकों) को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और सर्वसुविधा संपन्न जीवन देना केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक विकास की किरण इन आखिरी ढाणियों तक नहीं पहुंचती, तब तक विकास के तमाम दावे खोखले ही रहेंगे। सरकार के विकास को लेकर किए जा रहे दावों के बीच **पीके टाइम्स और लोक टुडे की टीम** ने करीब एक सप्ताह तक बॉर्डर इलाके के बाड़मेर जिले के मुनाबाव, बच्चियां, बन्ने की बस्ती और कबूल की ढाणी, सुंदरा, बाखासर, तालसर के साथ जैसलमेर जिले के लोंगेवाला, गजुओं की बस्ती, रणाऊ, लोंगेवाला, म्याजलार और फुलिया व शाहगढ़ बल्ज गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं जानीं तो हालात बेहद भयावह नजर आए। **पेश है बॉर्डर इलाके से खास रिर्पोट...**

शिक्षा की बदहाली: नौनिहालों का अंधकारमय भविष्य -

शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बॉर्डर इलाके दशकों पीछे छूटे हुए हैं। सीमांत क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, छतें टपकती हैं और बुनियादी ढांचे का नामोनिशान नहीं है। इन दूरदराज के स्कूलों में कोई भी शिक्षक नौकरी नहीं करना चाहता। जो नियुक्त होते हैं, वे लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं। एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। डिजिटल और कंप्यूटर शिक्षा तो यहाँ के बच्चों के लिए एक दूर का सपना मात्र है।

प्यास से सुलगता थार : सुखे जीएलआर, पानी के लिए तपते धोरों में मीलों का सफर

सरकार की हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं केवल जिला मुख्यालयों की फाइलों और होर्डिंग्स तक ही सीमित नजर आती हैं। जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज, तनोट, लोंगेवाला और बाड़मेर के गडरारोड, चौहटन व रामसर ब्लॉक के दर्जनों सीमांत गांवों में पीने के पानी की स्थिति अत्यंत भयावह है। गर्मियों में जब थार का तापमान 48 से 50 डिग्री पार कर जा चुका है, तब इन इलाकों की महिलाओं और बच्चों को रोज सुबह पीने के साफ पानी के लिए ऊंट-गाड़ों पर पीपे लादकर या सिर पर मटके रखकर 4 से 6 किलोमीटर दूर स्थित जीएलआर तक जाना पड़ रहा है। कई सीमावर्ती ढाणियों में हफ्तों तक सरकारी पानी की सप्लाई नहीं होती। ऐसे में गरीब ग्रामीणों को अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निजी वाटर टैंकर्स को देना पड़ता है, जो मनमाने दाम वसूलते हैं।

पलायन का दंश: ‘भूतिया गांवों’ में तब्दील होती सीमांत ढाणियां

मूलभूत सुविधाओं के इस भीषण अभाव, लगातार पड़ने वाले सूखे और रोजगार के शून्य अवसरों ने यहाँ की युवा पीढ़ी को हताश कर दिया है। परिणामस्वरूप, इन सामरिक गांवों से लोगों का शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। कई पारंपरिक ढाणियां अब पूरी तरह वीरान हो चुकी हैं, जिन्हें स्थानीय लोग ‘भूतिया गांव’ कहने लगे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों का इस तरह खाली होना देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि ये ग्रामीण ही सीमा पर होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहली सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंचाते थे।

टूटी सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए, तो अंदरूनी गांवों और ढाणियों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह जर्जर हैं या फिर रेत के ऊंचे-ऊंचे धोरों में विलीन हो चुके हैं। इन रास्तों पर साधारण वाहनों का चलना नामुमकिन है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप-केंद्र या तो बने ही नहीं हैं, और जहाँ बने हैं वहाँ ताले लटके रहते हैं। डॉक्टरों, स्टाफ और जीवन रक्षक दवाइयों का घोर अभाव है। किसी आपातकालीन स्थिति, प्रसव पीड़ा या सांप के काटने जैसी घटनाओं में मरीजों को आज भी ग्रामीण चारपाई (डोली) पर लादकर मुख्य सड़क तक लाते हैं। वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाते समय कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

‘डेजर्ट नेशनल पार्क’ कानून बना रुकावट

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में नेटवर्क टावर और पक्की सड़कों के निर्माण में डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) और वन विभाग के कड़े नियम सबसे बड़ी बाधा हैं। सुरक्षा और पर्यावरण के कड़े नियमों के पेंच में यहां की जनता पिछले कई दशकों से पिस रही है।

ग्रामीणों की कड़कती आवाज: ‘हम सिर्फ वोट बैंक हैं’

हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो दूर, फोन पर बात करने के लिए दो किलोमीटर दूर ऊंचे टीले पर जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं।

- तगाराम, निवासी, बन्ने की बस्ती (बाड़मेर)

बॉर्डर पर तारबंदी की लाइटें तो चमकती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अंधेरा है। सुविधाओं के लिए गहने तक बेचने की नौबत आ जाती है। सरकार के लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं। हमें सिर्फ चुनाव के वक्त याद करती है।

- रहीम खान, निवासी, शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र (जैसलमेर)

दो टूक- टूटते भरोसे के वेंटिलेटर पर देश की परीक्षा व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को 'राष्ट्रीय आपदा' की तरह नहीं देखेगी, तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026, सीबीएसई ओएसएम विवाद और एसएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा।

भारत में परीक्षा अब केवल योग्यता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णायक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार संदिग्ध हो जाए, जब मेहनत और ईमानदारी की जगह 'जुगाड़' और 'माफिया नेटवर्क' हावी हो जाएं, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है। पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जीडी परीक्षा में धांधली, ये घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब गहरे संस्थागत संकट में फंस चुकी है और भारत की परीक्षा प्रणाली अब वेंटिलेटर पर है। नीट-यूजी 2026 का घटनाक्रम तो इस विफलता की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। लगभग 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और वर्षों की तैयारी एक झटके में शून्य हो गई। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था, जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार मामला केवल बाहरी गिरोहों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जांच में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर तक मिलीभगत के आरोप सामने आए। सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। जिस संस्था को निष्पक्षता की गारंटी देनी थी, वही यदि धांधली का हिस्सा बन जाए तो पूरी व्यवस्था का नैतिक आधार ही खत्म हो जाता है। नीट पेपर लीक की प्रकृति भी सामान्य नहीं थी। 'गेस पेपर' के नाम पर लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का हूबहू मिल जाना, परीक्षा से पहले 600 अंकों तक के सवालों का प्रसार, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम प्रश्नपत्र का घूमना, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकते। यह एक संगठित, बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क का संकेत है, जो परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी को भेद चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में पेपर लीक के बाद भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है।

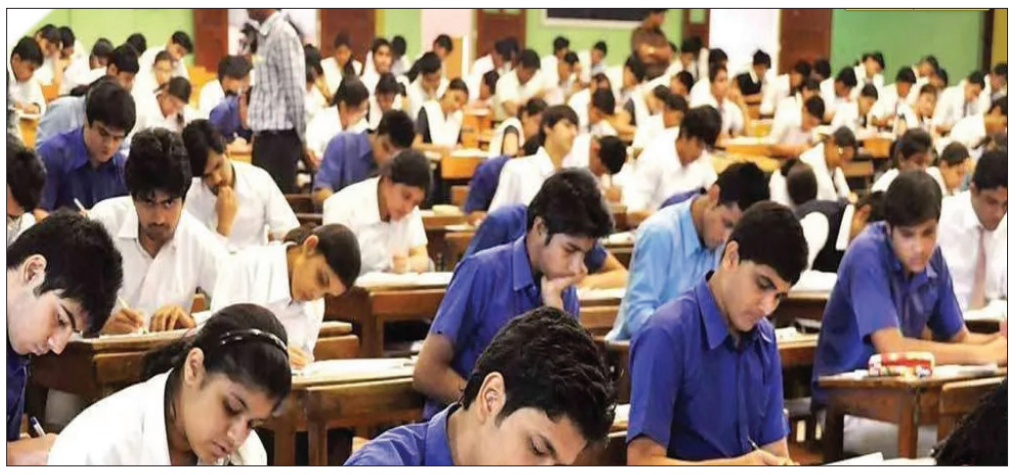

भारत की परीक्षा प्रणाली का ढ़ांचा ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही वह जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जड़ें जमाता है। जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में फैल सकता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कागजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। दूसरी ओर, कोचिंग उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं अब हजारों करोड़ रुपये का बाजार बन चुकी हैं। इस बाजार में 'सफलता' एक उत्पाद है, जिसे खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया 'सीक्रेट पेपर', '100 प्रतिशत सलेक्शन गारंटी' और ह्यइनसाइडर एक्सेसह्न जैसे झूठे वादों के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है।

यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट करता है। डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन इसके परिणाम उलटे दिखाई दिए। पास प्रतिशत में गिरावट, मेधावी छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलना और स्कैन की गई कॉपियों में भारी गड़बड़ियां, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तकनीक को बिना पर्याप्त तैयारी और परीक्षण के लागू किया गया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी कॉपियां धुंधली थी, कुछ को गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिली और कुछ मामलों में तो पूरी कॉपी ही किसी और की थी। यह स्थिति केवल तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती बल्कि यह सरासर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। यदि एक छात्र की मेहनत को किसी दूसरे की कॉपी से बदल दिया जाए तो यह केवल गलती नहीं है बल्कि उस छात्र के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड भले ही इन खामियों को सीमित मामलों तक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करें लेकिन छात्रों में बढ़ता असंतोष इस बात का प्रमाण है कि समस्या व्यापक है।

तीसरी बड़ी घटना, एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में धांधली, इस बात को और स्पष्ट करती है कि यह संकट किसी एक परीक्षा या संस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रैकेट ने इस धांधली के आधुनिक रूप को उजागर किया। प्रॉक्सी सर्वर, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा में हेरफेर किया जा रहा था। यह पारंपरिक नकल या पेपर लीक से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रणाली को भीतर से हैक किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक भयावह तस्वीर उभरती है, एक ऐसी व्यवस्था, जहां प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं, मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सबसे अधिक पीड़ित वह छात्र है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र, जिनके माता-पिता ने कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर उन्हें कोचिंग दिलाई, आज सबसे ज्यादा निराश हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता बल्कि यह मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और आत्मविश्वास के टूटने का कारण बनता है।

इस पूरे संकट का एक और खतरनाक पहलू है व्यवस्था के प्रति बढ़ता अविश्वास। जब छात्र यह मानने लगें कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि 'सेटिंग' से मिलती है तो यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी पतन है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या हर बार जांच, गिरफ्तारी और बयानबाजी से काम चल जाएगा? स्पष्ट है कि नहीं। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में पूर्ण डिजिटल और एन्क्रिप्टेड मॉडल लागू करना होगा। प्रश्नपत्रों को परीक्षा से कुछ मिनट पहले तक सुरक्षित सर्वर में रखा जाए और सीधे केंद्रों पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाए। इससे छपाई और परिवहन से जुड़ी कमजोरियां समाप्त होंगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को सीमित करना होगा। संवेदनशील कार्यों में केवल प्रशिक्षित और जवाबदेह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, पेपर लीक को संगठित आर्थिक अपराध घोषित कर इसके लिए गैर-जमानती कठोर कानून बनाए जाएं। जब तक अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह धंधा बंद नहीं होगा। चौथा, साइबर निगरानी को मजबूत करना होगा। टेलीग्राम, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए विशेष एजेंसियां बनाई जानी चाहिए। पांचवां, तकनीक को लागू करने से पहले उसका व्यापक परीक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीबीएसई ओएसएम विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना तैयारी के लागू की गई तकनीक समाधान नहीं बल्कि नई समस्या बन सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को 'राष्ट्रीय आपदा' की तरह नहीं देखेगी, तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026, सीबीएसई ओएसएम विवाद और एसएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। और जिस राष्ट्र के युवा ही अपनी व्यवस्था पर विश्वास खो दें, उसके भविष्य की नींव कितनी कमजोर हो जाती है, यह समझना मुश्किल नहीं है।

संपादकीय

नशे पर शिकंजा

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं।

चिंतन-मनन

भलाई का भाव होता है यज्ञ

एक भाव होता है मेरा दूसरा है मेरे लिए और तीसरा है सबके लिए। मेरा में इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है और ये पक्का कर लेता है कि मेरे पास जो है, वो केवल मेरा है, मैंने कमाया है, मुझे मिला है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यह सोच अज्ञानी लोगों की होती है, जो हमारे अहंकार को बनाये रखती है। मेरे लिए अर्थात इंसान सोचता है कि जो भी मेरे पास है, ये मेरा नहीं बल्कि मेरे लिए है। इसका स्वामी मैं नहीं बल्कि ये सब मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिला है। वो इसी भाव को मन में रखता है। यह सोच मध्यम दर्जे के लोगों की होती हैं।

तीसरा भाव है सबके लिए मतलब जो मेरे पास है, वो मेरा ही नहीं और मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विचार उत्तम दर्जे के इंसानों का होता हैं। इसी को यज्ञ कहा जाता है। जब मन में सबकी भलाई का भाव हो वही यज्ञ है। जो सबका ध्यान रखकर बाद में अपना सोचता है वही श्रेष्ठ इंसान है। इस तरह का यज्ञ अहंकार को गला देता है। ऐसी भावना के साथ साधना करने वाला ब्रह्म को पा लेता है। जो मनुष्य केवल मेरा-मेरा में ही फंसा रहता है, वो ना तो इस जन्म में सुख पाता न ही मरने के बाद परलोक में।

डिजिटल आक्रामकता के जाल में फंसा बचपन

दिलीप कुमार पाठक

आजकल घरों में शाम के वक्त एक खामोश नजारा दिखाई देता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में, एक ही सोफे पर साथ बैठा होता है, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती। सब के सब चुपचाप अपने-अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। माता-पिता भी इस बात से बड़े खुश और बेफिक्र रहते हैं कि उनका बच्चा बाहर धूप या धूल-मिट्टी में नहीं घूम रहा है, बल्कि घर के अंदर आराम से सुरक्षित बैठा है। लेकिन क्या कभी हमने ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचने की कोशिश की है कि स्क्रीन में अपनी आंखें गड़ाए बैठा हमारा यह मासूम बच्चा अंदर ही अंदर किस मानसिक दौर से गुजर रहा है? कहीं उसके नन्हें दिमाग पर नकारात्मक असर तो नहीं हो रहा?

हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पुराने जमाने में जब इस दिन की चर्चा होती थी, तो बच्चों पर अत्याचार का सीधा सा मतलब लड़ाई-झगड़े, युद्ध, दंगे या फिर फैक्ट्रियों में होने वाली बाल-मजूदरी से लगाया जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में मासूमों के खिलाफ होने वाली हिंसा का पूरा चेहरा ही बदल चुका है। अब यह आक्रामकता सड़क पर शोर नहीं मचाती। अब यह हिंसा बिना किसी आवाज के, इंटरनेट के महीन रास्तों से रेंगती हुई सीधे हमारे घरों के भीतर और हमारे बच्चों के दिमाग पर सीधा हमला कर रही है। जरा रुककर गंभीरता से सोचिए। आपका बच्चा आपके ठीक सामने बैठा हो सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ठीक उसी वक्त उसका कोमल मन किसी बहुत गहरे तनाव या डर में डूब रहा हो। ऑनलाइन गेम खेलते समय किसी अनजान शख्स द्वारा दी गई गंदी गालियां, सोशल मीडिया पर दोस्तों द्वारा उड़ाया गया उसका कोई भद्दा मजाक, या फिर इंटरनेट के समंदर में छिपे किसी अपराधी की गंदी नजर। यह डिजिटल आक्रामकता ऐसी होती है जो बाहर से शरीर पर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके जख्म और भी ज्यादा गहरे होते हैं। यह अदृश्य हमला बच्चे के आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। सबसे ज्यादा डरावना तो यह है कि इंटरनेट के इस गंदे खेल में कोई तीसरा देखने वाला गवाह नहीं होता, सिवाय उस एक सहमे हुए और अकेले पड़ चुके बच्चे के।

वैश्विक संस्था यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर तीसरा इंसान असल में एक बच्चा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी ऑनलाइन किसी न किसी रूप में मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार होती है। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में बच्चों को रोने से रोकने या उन्हें शांत बैठाने के लिए खिलौने की जगह मोबाइल थमा देते हैं। यह डिजिटल झुनझुना शुरू-शुरू में तो हमें बड़ी राहत देता है, लेकिन धीरे-धीरे यही मोबाइल बच्चे और माता-पिता के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है। जब बच्चा इंटरनेट की किसी बड़ी मुसीबत या ब्लैकमेलिंग में फंसता है, तो वह लोक-लाज और डर के मारे अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बता पाता। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है। अब वह समय आ गया है जब हमें इस बढ़ते हुए खतरे को गहराई से समझना होगा। यह कोई ऐसी सामाजिक समस्या नहीं है जो केवल पुलिस की मुस्तैदी या सरकार के कड़े कानून बना देने भर से ठीक हो जाएगी। इस बीमारी के इलाज की शुरूआत हमारे अपने घर के भीतर से ही होगी। बच्चों को महंगे स्मार्टफोन या गैजेट्स लाकर देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें अपना कीमती वक्त देना। अपने बच्चों के बदलते हुए बर्ताव पर हमेशा नजर रखिए। अगर आपका हंसता-खेलता बच्चा अचानक गुमसुम रहने लगा है, बात-बात पर गुस्सा कर रहा है या आपसे अपना फोन छिपाने लगा है, तो उसे डांटने या मारने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। उसके पास बैठिए, प्यार से हाथ थामिए, उससे खुलकर बातें कीजिए और उसे यह भरोसा दिलाइए कि दुनिया की चाहे जो भी मुसीबत हो, उसके मम्मी-पापा हमेशा उसके साथ खड़े हैं। इस देश के बचपन को सुरक्षित और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए, इस डिजिटल दौर में अपने बच्चों के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बनें। उनके हाथ से कुछ देर के लिए फोन छीनकर उन्हें पास के मैदान में खेलने के लिए भेजें, रात को सोने से पहले उनसे गप्पें मारें और उन्हें खुलकर हंसने का असली मौका दें। जब तक हम उनके लिए घर में एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक स्क्रीन के पीछे का यह रोना कभी बंद नहीं होगा। हमारे देश का उज्ज्वल भविष्य मोबाइल की इस छोटी सी स्क्रीन में घुट-घुट कर जीने के लिए नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे खुलकर जिंदगी जीने के लिए है।

कमजोर मानसून तो महंगाई का लगेगा तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पायें हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरुरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कूलरों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। जल बचाओ मात्र स्लोगन ही रह गया है और इसका असर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना सफल रहा है वह सामने हैं। बाहरमासी नदी नालें तो अब कल्पना की बात हो गए हैं बल्कि बरसाती नदियां भी बरसात में एकाध बार ही पूरे वेग से बहती दिखती है। ऐसे में गंभीरता को तो समझा ही जा सकता है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि मानसून हमेशा सामान्य ही रहेगा यह सोचना अपने आप में गलत होगा। जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं वह किसी और की देन नहीं हमारे कारण ही हो रहा है। हालात यह हो गए हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं और गर्मी में गर्मी को तरसने लगे हैं। यहां तक कि इस बार तो बसंत की प्रतीक्षा ही करते रह गए हैं। जनवरी फरवरी में सर्दी तो फिर मार्च अप्रेल में गर्मी का असर देखा गया। बसंत कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कहने का अर्थ है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम सामने हैं। प्राकृतिक विपदाएं अधिक होने लगी है। ग्लेसियरों में तेजी से बर्फ पिघल रही है, समयपर बर्फवारी कम होने लगी है। बेमौसम आंधी ओलावृष्टि आम होती जा रही है। खैर यह विषयांतर होगा पर कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी ताकि कमजोर मानसून का जनजीवन और अर्थ व्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़े। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

दवा नहीं, कायाकल्प: बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए रामबाण 'पंचकर्म'

भागदौड़ भरी जिंदगी में पनपी बीमारियों का हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से करवा रहे इलाज

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बढ़ी मरीजों की संख्या

प्रमोद कुमार। जयपुर

भागदौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव और अनियमित खानपान के कारण बढ़ती लाइफस्टाइल बीमारियों के बीच लोग अब फिर से हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं। इस बदलाव के केंद्र में है 'पंचकर्म' चिकित्सा, जिसे सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (हृद्ध) में इन दिनों देश-विदेश से बड़ी संख्या में मरीज पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पंचकर्म क्या है, यह कैसे काम करता है और किन बीमारियों में यह सबसे ज्यादा कारगर है। पेश है खास रिर्पोट...

क्या है पंचकर्म?

पंचकर्म आयुर्वेद की एक विशेष डिटॉक्सिफिकेशन (विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने) और कायाकल्प चिकित्सा है। यह शरीर में बढ़े हुए 'दोषों' (वात, पित्त और कफ) को संतुलित कर बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें मुख्य रूप से पांच क्रियाएं शामिल हैं।

वमन: कफ दोष को दूर करने के लिए कराई जाने वाली औषधीय उल्टी।

विरेचन: पित्त दोष को साफ करने के लिए दस्त के जरिए पेट की शुद्धि।

बस्ति: वात रोगों को ठीक करने के लिए औषधीय तेल या काढ़े का एनिमा।

नस्य: सिर, गले और श्वसन तंत्र की शुद्धि के लिए नाक में औषधीय तेल डालना।

रक्तमोक्षण: दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना (जैसे जोंक या थेरेपी के जरिए)।

कैसे काम करती है यह थेरेपी?

पूर्व कर्म (तैयारी): इसमें 'स्नेहन' (औषधीय घी/तेल पिलाना व मालिश) और 'स्वेदन' (भाप देना) शामिल है। इससे शरीर के कोने-कोने में जमे टॉक्सिन्स पिघलकर पेट और आंतों में आ जाते हैं।

प्रधान कर्म (मुख्य प्रक्रिया): इस चरण में मरीज की जरूरत के अनुसार ऊपर बताए गए पांच मुख्य कर्मों (वमन, विरेचन आदि) में से सही थेरेपी देकर टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है।

पश्चात कर्म (देखभाल): टॉक्सिन्स निकलने के बाद पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए मरीज को विशेष खानपान (पेय पदार्थ से लेकर ठोस भोजन तक) और आराम की सलाह दी जाती है।

इन बीमारियों में रामबाण है पंचकर्म -

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार, पंचकर्म का उपयोग न केवल बीमार होने पर, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए भी किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से गठिया, साइटिका, स्लिप डिस्क और पुराने कमर दर्द में बस्ति और पोटली थेरेपी बहुत राहत देती है। तनाव, एंग्जायटी, अनिद्रा और माइग्रेन में 'शिरोधारा' और 'नस्य' कमाल का असर दिखाते हैं। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर को नियंत्रित करने में यह मददगार है। सोरायसिस, एक्जिमा, पुराना कब्ज और एसिडिटी के मरीजों को विरेचन और रक्तमोक्षण से बहुत फायदा होता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बढ़ी मरीजों की संख्या -

जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (हृद्ध) आज के समय में प्रामाणिक पंचकर्म चिकित्सा का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। डॉक्टरों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में यहां पंचकर्म कराने वाले मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान में विशेषज्ञों की देखरेख में बेहद किफायती दरों पर यह थेरेपी दी जा रही है। लोग न सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, बल्कि अपने शरीर को रीबूट और रीहैलथ करने के लिए भी यहां 'वेलनेस पंचकर्म' का सहारा ले रहे हैं। अलवर निवासी 12 वीं क्लास के छात्र का वजन 150 किलो हो गया, जिन्होंने दिल्ली के कई हॉस्पिटल व जयपुर एसएमएस में उपचार कराया। जहां फायदा नहीं होने पर वे राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में इलाज करवा रहे हैं, जहां कुछ ही महीनों में 40 किलो वजन कम हो गया है। पंचकर्म विभाग के ॥शष्ठ डॉ. गोपेश मंगल ने बताया कि हर व्यक्ति के लिए पंचकर्म की प्रक्रिया अलग हो सकती है और बिना चिकित्सकीय सलाह के इसे अपनाना नुकसानदायक भी हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, बेसमेंट में फंसे 3 लोग सुरक्षित निकाले गए

नईदिल्ली, एजेंसी। मालवीय नगर के हौजरानी स्थित एक रेस्तरां में बुधवार सुबह आठ बजे आग लग गई। धुएं और आग के बीच बेसमेंट में तीन लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड के अनुसार, सुबह 8.50 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी रेस्तरां में फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के डिविजनल ऑफिसर रविंदर मौके पर मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

54 लाख रुपये की डकैती मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, छह बदमाशों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से गन प्वाइंट पर 54.50 लाख रुपये डकैती डालने के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ सफलता लगी है। उत्तरी जिला पुलिस ने बुधवार को छह बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने कुछ दिन पहले ही कार सवार व्यापारियों से बदमाशों ने लूटपाट की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में व्यापक अंतरराज्यीय अभियानों के बाद की गईं। लूट की रकम के 50 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि 26 मई 2026 को पीएस लाहौरी गेट में 54.5 लाख रुपये की डकैती हुई थी।

दिल्ली के सतबड़ी गांव में 2.16 करोड़ से सुधरेगा ड्रेनेज, जलभराव से मिलेगी राहत

नईदिल्ली, एजेंसी। छतरपुर विधानसभा स्थित सतबड़ी गांव की लगभग 10 हजार की आबादी को अब जल्द ही राहत मिल सकती है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत गांव की नालियां और ड्रेनज व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसके लिए कुल 2.16 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में इन दिनों विकास कार्य भी तेजी से कराए जा रहे हैं। आगामी मानसून को देखते हुए जलभराव की समस्या के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद उमेद फोगाट आदि रहे।

विशेष विवाह अधिनियमः दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में अहम निर्णय पारित करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विशेष स्थिति में तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए एक साल के इंतजार की अवधि को माफ किया जा सकता है। पारिवारिक अदालत के निर्णय को रद करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में जहां शादी सिर्फ नाम की हो और समाज या परिवार से कोई मंजूरी न मिली हो, वहां कानूनी इंतजार की अवधि पर अड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। पति ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कानूनी अवधि में छूट देने की अर्जी को खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी थी। यह मामला अलग-अलग धर्मों से जुड़े युगल जोड़े से जुड़ा है।

सोना बेचने की खबर पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा, पूछा- क्या देश का सोना भी बिक गया?

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के स्वर्ण भंडार को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है और यदि ऐसा है तो इसकी वजह क्या है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार को किए गए पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि यदि यह खबर सही है कि देश के सोने का एक हिस्सा बेच दिया गया है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि यदि देश के पास रखा सोना बेचना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आप प्रमुख ने कहा कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ नहीं बता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश की वास्तविक परिस्थितियों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को यहीं रहना है और उन्हें देश की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी मिलनी चाहिए। दरअसल, केजरीवाल ने अपने पोस्ट के साथ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान युद्ध के कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए भारत के केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा कम किया हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सरकारी कर्मी के उच्च योग्यता छिपाने पर बर्खास्तगी की संभावना परखेगा सुप्रीम कोर्ट, जांच के बाद होगा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। क्या एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी के लिए निर्धारित डिग्री से अधिक उच्च योग्यता छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के एक फैसले की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के केंद्र के निर्णय को बरकरार रखा था। उसने 'दसवीं पास' मानदंड से अधिक 'इंटरमीडिएट पास' होने की जानकारी छिपाई थी, जो 'कार्य सहायक' की नौकरी के लिए आवश्यक थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, अरविंद कुमार और श्री चंद्रशेखर की पीठ ने पवार सुभाष की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने हाई कोर्ट के 27 नवंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ ने सुभाष के लिए उपस्थित वकील से कहा, 'यह निर्णय प्रथम दृष्टया गलत है। हम इस निर्णय की जांच करेंगे। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जो कहता है कि उच्च योग्यता अयोग्यता का आधार नहीं हो सकती। '

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता ने 'कार्य सहायक' के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए निर्धारित योग्यता 'दसवीं पास' थी और उसने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह पहले से ही 'इंटरमीडिएट पास' था। इसने कहा कि सुभाष ने 2003 में 10वीं कक्षा पास की और 2006 में इंटरमीडिएट किया और 26 जुलाई, 2010 को इस पद के लिए आवेदन किया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुभाष द्वारा किए गए घोषणा के आधार पर उसे नौकरी के लिए शार्टलिस्ट किया गया। आवेदन के चरण में और बाद की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इसे 'जानबूझकर जानकारी छिपाने' के रूप में मानते हुए केंद्र सरकार ने 27 मई, 2013 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

सुभाष ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी, जिसने 27 मई, 2013 के आदेश को रद कर दिया और मामले को वापस भेजते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उसे सार्वजनिक रोजगार में रखने के पहलू पर पुनर्विचार करे, जिसके लिए वह अन्यथा योग्य था और एक स्पष्ट आदेश पारित करे।

सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए 30 अप्रैल, 2022 को एक स्पष्ट विस्तृत आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक रोजगार के लिए अनुपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ड्रग्स बेचने वाले लोगों से बेहद सख्ती से निपटना होगा क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार एक आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस शील नागू और जस्टिस वी. मोहना की पीठ एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यूक्रेन पर रूस ने दागीं दर्जनों मिसाइलें; हमले में 18 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

कीव, एजेंसी। रूस ने बीती रात यूक्रेन के कीव और दूसरे शहरों पर सैकड़ों ड्रोन व दर्जनों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 131 व्यक्ति घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के हफ्तों में मॉस्को के हवाई हमलों का अभियान तेज करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य यूक्रेन में अमेरिकी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों की कमी का फायदा उठाना और रूस में बढ़ती निराशा के बीच लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि चार साल से जारी युद्ध में देश बढ़त बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मध्य यूक्रेन के शहर ड्नीप्रो में अपार्टमेंट इमारतों के मलबे में खोजबीन कर रही आपातकालीन बचाव टीमों ने तीन वर्षीय बच्चे, एक महिला और उसके आठ वर्षीय बेटे के शव बरामद किए। हमले सुबह होने के बाद तक जारी रहे और विभिन्न शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। अधिकारियों ने बताया कि ड्नीप्रो में 12 लोगों और कीव में छह लोगों की मौत हुई है। रूस की ओर से बड़े हवाई हमले की चेतावनी दिए जाने और विदेशी राजनयिकों को यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद से शहर के निवासी कई दिन से चिंतित थे। हालांकि किसी भी राजनयिक ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस के इस व्यापक हमले से स्पष्ट संदेश मिला है कि यदि यूक्रेन को बैलिस्टिक और अन्य मिसाइल हमलों से सुरक्षा नहीं दी गई, तो ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिक समर्थन की अपील की। रूस की रणनीति यूक्रेन में अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइलों की कमी का फायदा उठाने की है। ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय भंडार भी कम हो गए हैं। इसकी वजह से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से लोगों का बचाव मुश्किल हो गया है।

अमेरिकी सांसद की चेतावनी: वीजा में देरी से यूएस में डॉक्टरों की कमी का खतरा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रैंड ने चेतावनी दी है कि जे-1 वीजा छूट की प्रक्रिया में देरी के कारण विदेश में प्रशिक्षित सैकड़ों डॉक्टरों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी और बढ़ सकती है।

न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट प्रतिनिधि गिलिब्रैंड ने अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रशासनिक लंबित मामलों के कारण योग्य विदेशी डॉक्टर देशभर के अस्पतालों में नौकरी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसमें न्यूयॉर्क के कई ग्रामीण और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्र भी शामिल हैं। गिलिब्रैंड ने लिखा, 'ऑफिस ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में प्रशासनिक रुकावट के कारण सैकड़ों योग्य विदेशी डॉक्टर अमेरिका में अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पा रहे हैं।' यह मुद्दा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स में भारतीय डॉक्टरों की संख्या सबसे अधिक है।

गिलिब्रैंड ने कहा कि न्यूयॉर्क राज्य डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों पर काफी निर्भर है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डॉक्टरों की भर्ती करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स न्यूयॉर्क की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

दुनियाभर के दुर्लभ खनिज पर नजरें गड़ाए है अमेरिका! मार्को रूबियो बोले- हमारी कूटनीति का प्रमुख आधार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) अब अमेरिकी कूटनीति का एक प्रमुख आधार बन गए हैं। दुनिया भर में स्थित अमेरिकी दूतावास अब आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने और चीन पर निर्भरता कम करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

मार्को रूबियो ने कहा, 'दुनिया भर में हर अमेरिकी दूतावास में महत्वपूर्ण खनिज हमारी कूटनीति का एक प्रमुख हिस्सा हैं।' उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों को उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा प्रणालियों, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया।

उन्होंने बताया कि अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाएं विकसित कर रहा है, ताकि खनन, शोधन और प्रसंस्करण में चीन के वर्चस्व से पैदा हुई कमजोरियों को कम किया जा सके। उन्होंने हाल की कूटनीतिक पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें खनिज सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय बैठकें शामिल हैं।

रूबियो ने कहा, 'दुर्लभ खनिज को लेकर मंत्रिस्तरीय बैठक में तीन

दर्जन से अधिक देशों ने भाग लिया था।' उनके अनुसार, अमेरिका की रणनीति केवल खनिज भंडारों तक पहुंच हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन के बाहर प्रसंस्करण और शोधन क्षमता बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि इन सामग्रियों को इस्तेमाल योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यह आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का अहम हिस्सा है। रूबियो ने बताया कि अमेरिकी राजनयिक अब दुनियाभर की सरकारों के साथ मिलकर आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों की पहचान कर रहे हैं और देशों को निवेश तथा विकास के वैकल्पिक स्रोतों से जोड़ने का काम कर रहे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास की तलाश करने वाले कई देशों के पास अक्सर चीन समर्थित परियोजनाओं के अलावा बहुत कम विकल्प होते हैं। रूबियो ने कहा, 'वहां केवल चीनी कंपनियां ही पहुंचती हैं।' उन्होंने इसे कई विकासशील देशों के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसी कारण अमेरिका खनन, प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी और सहयोगी देशों के विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के तहत वित्तीय साधनों और समान सोच वाले देशों के साथ साझेदारी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, 17 विद्रोही मारे गए

क्वेटा, एजेंसी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पिछले हफ़्ते अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में एक शटल ट्रेन पर हुए बम हमले के बाद कम से कम 17 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया है। 24 मई को क्वेटा के पास एक स्टेशन पर शटल ट्रेन पर हुए संदिग्ध वाहन-जनित आत्मघाती हमले में तीन सुरक्षा कर्मियों सहित कम से कम 16 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार, इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के विभिन्न ज़िलों में कई खुफ़िया-आधारित अभियान चलाए, जिनमें 17 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने मस्तंग, नुश्की, ज़हरी, खुज़दार और केच में चलाए गए अभियानों के दौरान आतंकवादियों के कई ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि फ़ितना-अल-हिंदोस्तान से जुड़े आतंकवादियों के साथ हुई भारी गोलीबारी में उनमें से 17 आतंकवादी मारे गए। आईएसपीआर ने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद, भारी मात्रा में विस्फोटक और तैयार इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए हैं। मारे गए ये आतंकवादी इस क्षेत्र में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे।

तिब्बत में चीन के अत्याचारों की जांच करेगा अमेरिका: संसद में नया बिल पेश

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने एक नया बिल पेश किया है। इस बिल के तहत अमेरिकी विदेश विभाग को यह तय करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं।

यह बिल न्यू जर्सी के रिपब्लिकन प्रतिनिधि क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम सुओजी ने मंगलवार को पेश किया। इस बिल का नाम 'टिब्बत एट्रोसिटीज डिटरमिनेशन एक्ट' है। अगर यह पास हो जाता है, तो विदेश मंत्री को एक साल के अंदर कांग्रेस को एक रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें चीन की तिब्बत में की गई गतिविधियों का आकलन होगा। यह बिल सीनेट में पहले से पेश किए गए एक दूसरे बिल का ही हाउस वर्जन है, जिसे रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले ने पेश किया था। अगर यह कानून बन जाता है, तो अमेरिकी विदेश विभाग को यह जांच करनी होगी कि क्या चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों के खिलाफ

मनमानी हत्याएं, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान, अमानवीय जीवन स्थितियां, जबरन विस्थापन, बड़े पैमाने पर हिरासत में लेना, जबरन नसबंदी और गर्भपात, और तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों और समुदायों से अलग करने जैसे अत्याचार किए हैं। इसके अलावा, यह भी देखा जाएगा कि चीन तिब्बती बौद्ध धर्म को अपने हिसाब से बदलने, तिब्बती भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। रिपोर्ट में सरकारी जानकारी के साथ-साथ दूसरे स्वतंत्र स्रोतों की जानकारी भी शामिल होगी। साथ ही यह भी सुझाव दिए जाएंगे कि अमेरिका क्या कदम उठा सकता है, जैसे कि प्रतिबंध, वीजा रोकना या कूटनीतिक कार्रवाई करना।

क्रिस स्मिथ ने कहा कि चीन लंबे समय से तिब्बत में गंभीर अत्याचार करता आ रहा है। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इन अपराधों को साफ तौर पर सामने लाना जरूरी है। क्योंकि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। टॉम सुओजी ने कहा कि चीन की कार्रवाई सिर्फ तिब्बत ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बतियों, उइगर मुसलमानों और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के साथ हो रहे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तिब्बत में हो रहे कथित अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

6 मंजिला असुरक्षित बिल्डिंग: 23 दिनों का खौफ, 1 मिनट में जमींदोज !

पिलर क्षतिग्रस्त होने पर एक तरफ झुक गई थी इमारत, गिरने पर जोरदार धमाका होने के साथ पूरे इलाके में छाई धूल

लोक टुडे। जयपुर

जयपुर के रामगंज क्षेत्र के चीता वालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान एक तरफ झुक चुकी 6 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुरक्षित तरीके से ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह 10:18 बजे पूरी तकनीकी प्रक्रिया और पुख्ता सुरक्षा मानकों के तहत की गई। जैसे ही बिल्डिंग को गिराया गया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे रामगंज इलाके में धूल का भारी गुबार छा गया। बिल्डिंग को गिराने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। बिल्डिंग के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया था। बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। आसपास के 10 से 15 मकानों को खाली कराकर वहां रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। लाइट बंद कर दी गई थी। इस दौरान रामगंज थाना पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो सामने वाली इमारत में भी थोड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ ही बिल्डिंग के नजदीक एक पेड़ भी टूट गया।

बिना परमिशन के बनाई थी बिल्डिंग -

नगर निगम किशनपोल जोन उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया- 6 मंजिला बिल्डिंग को बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से यहां बनाया गया था। 9 मई को बिल्डिंग के एक हिस्से में दरार आ गई थी।

उसी दिन इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने विशेषज्ञों से राय ली। विशेषज्ञों ने इसे असुरक्षित माना। इसके बाद आज इस बिल्डिंग को गिराया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा- बिल्डिंग गिराने की प्रक्रिया पूरी सावधानी और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की गई। आसपास की इमारतों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया।

बिल्डिंग में 30 से ज्यादा लोग रहते थे -

निगम के अधिकारी ने बताया कि यह बिल्डिंग करीब 10 से 15 साल पुरानी थी। इसमें पहले 4 मंजिल बनी हुई थीं। पांचवीं और छठी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। इस बिल्डिंग में दो दुकान भी थीं। दुकान के शटर में भी बैंड आ गया था। मकान मालिक रईस ने बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्सों को कई लोगों को किराए पर दे रखा था। बिल्डिंग में 30 से ज्यादा लोग रहते थे।

बिजली और रास्ते किए बंद :

एहतियातन तौर पर पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और बैरिकेडिंग लगाकर आम लोगों व वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान रामगंज थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर अलर्ट मोड में तैनात रहीं।

इसलिए गिराई गई बिल्डिंग -

यह निर्माणाधीन इमारत करीब 23 दिन पहले (9 मई को) तकनीकी खामी और पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण एक तरफ झुक गई थी। इसके बाद से ही स्थानीय निवासियों में डर का माहौल था। नगर निगम की तकनीकी टीम और विशेषज्ञों ने जांच के बाद इस बिल्डिंग को 'बेहद खतरनाक और असुरक्षित' घोषित किया था, जिसके बाद इसे जमींदोज करने का अंतिम फैसला लिया गया। अच्छी बात यह रही कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई इस कार्रवाई में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है।

राज्यसभा चुनाव : बीजेपी से सतीश पूनिया व अलका गुर्जर उम्मीदवार

दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास, तीन सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी

लोक टुडे। जयपुर

राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान के दो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा प्रभारी और अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं। दरअसल, राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या के गणित के हिसाब से बीजेपी दो सीटों पर ही चुनाव जीत सकती है। तीन सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस कारण तीन सीट खाली हो रही है।

दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास -

सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने राजस्थान के दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास किया है। सतीश पूनिया के जरिए जाट और अलका गुर्जर के जरिए गुर्जर वोटर्स को साधने की रणनीति है। दोनों ही नेता लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं।

सतीश पूनिया को राज्यसभा टिकट के सियासी मायने -

सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहने के साथ संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूनिया को हाईकमान ने अन्य राज्यों में जिम्मेदारी दी। बिहार चुनावों में जिम्मेदारी देने के बाद उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया। अब उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर पार्टी के भीतर भी मैसेज दिया है।

अलका गुर्जर एक बार मंत्री रह चुकीं -

अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय है, एक बार विधायक और मंत्री रह चुकी है। अलका गुर्जर का परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा है। उनके पति डॉ नाथू सिंह गुर्जर बीजेपी सरकार के वक्त मंत्री रह चुके हैं। नाथू सिंह गुर्जर बीजेपी में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं।

जयपुर नगर निगम आयुक्त ने संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

आयुक्त ने परिवादियों से सीधा संवाद कर प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

जयपुर

जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की और परिवादियों से फ़ोन पर फीडबैक लिया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिकायतों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग करने की जरूरत हैं । आयुक्त कसेरा ने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से

जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में संपर्क हेल्पलाइन मील का पत्थर साबित हो रही है। आयुक्त कसेरा ने हेल्पलाइन पर परिवादियों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं को विस्तार और संवेदनशीलता से सुना। परिवादियों ने उन्हें टूटी सड़को के निर्माण/मरम्मत , जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में हुए नामों की गड़बड़ियों और पट्टे जारी करने ,सफाई व्यवस्था आदि से सम्बंधित शिकायतों के बारें में बताया। आयुक्त ने परिवादियों कि समस्याओ पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया। संपर्क पोर्टल के आंकड़ो के अनुसार अब तक जयपुर नगर निगम से सम्बंधित 91 हज़ार 753 प्रकरण दर्ज हुये है। उनमे से 87 हज़ार 884 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है जो कि लगभग 95.78 प्रतिशत है। विभाग द्वारा शिकायतों का औसत निस्तारण 18 दिवस में किया जा रहा है। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर सकते है।

जनकल्याणकारी प्रोजेक्ट भी भाजपा के 'इंतजारशास्त्र' और 'बदले की राजनीति' की भेंट चढ़ गया-अशोक गहलोत

जयपुर

जयपुर को जाम-मुक्त बनाने के विज़न के साथ हमारी कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021-22 में ओटीएस, रामबाग, जेडीए, जवाहर सर्किल, बीटू बाईपास, लक्ष्मीमंदिर और चौमू हाउस जैसे 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने का ऐतिहासिक काम शुरू किया था। बी-2 बाईपास और लक्ष्मीमंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर व अंडरपास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लेकिन संकीर्ण राजनीतिक सोच से ग्रस्त भाजपा सरकार ने आते ही ओटीएस चौराहे पर बनने वाले हैंगिंग ब्रिज का अनुबंध ही रद्द कर दिया! जनता रोज़ जाम में पिसती रही और यह जनकल्याणकारी प्रोजेक्ट भी भाजपा के 'इंतजारशास्त्र' और 'बदले की राजनीति' की भेंट चढ़ गया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने इस सोई हुई सरकार को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह परियोजना हमारी तत्कालीन सरकार की घोषणा के अनुरूप ही पूरी होगी। न्यायालय की यह टिप्पणी भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि 'सरकार बदलने से अनुबंध नहीं बदला जा सकता और राजनीतिक द्वेष में सरकारी वादे नहीं तोड़े जा सकते। '

आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान एवं चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में जोर

लोक टुडे। जयपुर

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में जापान के प्रतिष्ठित त्सुकुबा विश्वविद्यालय के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से संस्थान का विजिट किया। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के बीच भविष्य में समझौता ज्ञापन स्थापित करने तथा आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के उपाध्यक्ष प्रो. ओहनेदा ओसामु, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज की प्रो. इसोडा हिरोको तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की डॉ. फुकुशिगे मिजुहो शामिल थीं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से कुलसचिव प्रो. अनीता शर्मा, प्रो. हेमन्त कुमार (विभागाध्यक्ष, शल्य तंत्र), प्रो. अनुपम श्रीवास्तव (विभागाध्यक्ष, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग), जे.पी. शर्मा (संयुक्त निदेशक, प्रशासन) एवं चन्द्रशेखर शर्मा (उपनिदेशक) सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। विजिट के दौरान दोनों संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, विद्यार्थी एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों, शैक्षणिक सहयोग, वैज्ञानिक प्रकाशनों तथा समन्वित चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान अवसंरचना, अस्पताल सेवाओं तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अधिकारियों ने संस्थान द्वारा संचालित आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान एवं चिकित्सा सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

मगरे का शेर 'भाटी' : जाट समाज को आरक्षण देने पर छोड़ी 'भाजपा'

राजस्थान की राजनीति में देवी सिंह भाटी सिद्धांतों की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण

नीरज मेहरा। जयपुर

राजस्थान की राजनीति में जब भी दबंग छवि, स्पष्टवादिता और सिद्धांतों के लिए सत्ता को लात मार देने वाले नेताओं का जिक्र होगा, तो बीकानेर के देवी सिंह भाटी का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में आएगा। बीकानेर के आस-पास के पथरीले और ऊबड़-खाबड़ इलाके को भौगोलिक रूप से 'मगरा' नाम से जाना जाता है। इसी मगरा क्षेत्र में अपने जनहित के कार्यों और बेबाक अंदाज के कारण देवी सिंह भाटी को 'मगरे का शेर' कहा जाता है।

सात बार के विधायक और तीन बार के मंत्री का सफर

देवी सिंह भाटी का राजनीतिक जीवन बेहद गौरवशाली रहा है। वे लगातार सात बार विधायक चुने गए और तीन बार राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उनकी राजनीति कभी भी बंद कमरों या महलों की मोहताज नहीं रही, बल्कि वे सीधे जनता से जुड़े रहे। सामाजिक कार्यों और जनता की समस्याओं पर तुरंत कड़ा रुख अपनाना उनकी पहचान रही है।

सत्ता का त्याग: जाट आरक्षण और बीजेपी से बगावत

देवी सिंह भाटी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ साल 2003 के आसपास आया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जाट समाज को ओबीसी (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण दिए जाने के बाद, भाटी ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि आरक्षण का आधार जाति न होकर आर्थिक स्थिति होना चाहिए। सिद्धांतों के पक्के भाटी ने एक झटके में मंत्री पद पर रहते हुए अपनी ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। सत्ता सुख को दरकिनार कर वे सड़क पर उतर आए।

'सामाजिक न्याय मंच' का गठन और लोकेंद्र सिंह कालवी का साथ -

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (सवर्णों) के हक की लड़ाई लड़ने के लिए देवी सिंह भाटी ने राजपूत समाज के दिग्गज नेता स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने मिलकर साल 2003 में 'सामाजिक न्याय मंच' नामक एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। इस मंच का मुख्य एजेंडा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवाना था। सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले भाटी और कालवी ने पूरे राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सवर्ण समाज को एकजुट किया।

बीजेपी के खिलाफ माहौल और पार्टी से निष्कासन -

सामाजिक न्याय मंच ने तत्कालीन बीजेपी नेतृत्व और सरकार के खिलाफ राजस्थान के कोने-कोने में विशाल रैलियां कीं। भाटी की जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने बीजेपी आलाकमान की चिंताएं बढ़ा दी थीं। दोनों नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसा तीखा माहौल बनाया कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। शुरुआत में बीजेपी नेतृत्व ने भाटी के कड़े बयानों और विरोध को सहन किया, क्योंकि वे पार्टी के एक बेहद मजबूत स्तंभ थे। लेकिन जब भाटी ने सामाजिक न्याय मंच को एक पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में स्थापित कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू किया, तो अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

एक अमिट राजनीतिक विरासत -

पार्टी से निकाले जाने के बाद भी देवी सिंह भाटी का हौसला कम नहीं हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव में सामाजिक न्याय मंच ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समीकरण बिगाड़ दिए थे। हालांकि, समय चक्र बदला और सालों बाद भाटी की पुनः बीजेपी में वापसी भी हुई, लेकिन 2003 का वह दौर इतिहास में दर्ज हो गया जब एक नेता ने आर्थिक रूप से पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए मंत्री पद और अपनी स्थापित पार्टी को दांव पर लगा दिया था। आज भी मगरा क्षेत्र में उनकी यह दबंग और त्यागी छवि लोगों के दिलों में जिंदा है।

मानसून की दस्तक : केरलम पहुंचा, इस बार 3 दिन देरी से आया

लोक टुडे। जयपुर

मानसून केरलम पहुंच गया है। अगले 2-3 दिन यह गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर कर सकता है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के मुताबिक, केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी के असर से आंधी-बारिश देखने मिल सकती है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद डेढ़ महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)